Impact Factor 2.147

ISSN 2349-638x

Reviewed International Journal



AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (AIIRJ)

Monthly Publish Journal

VOL-III ISSUE- Mar. 2016

Address

- •Vikram Nagar, Boudhi Chouk, Latur.
- •Tq. Latur, Dis. Latur 413512
- (+91) 9922455749, (+91) 9158387437

Email

·aiirjpramod@gmail.com

Website

•www.aiirjournal.com

CHIEF EDITOR - PRAMOD PRAKASHRAO TANDALE

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)

Vol - III Issue-III MARCH 2016 ISSN 2349-638x Impact Factor 2.147

भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां

अर्शदीप सिंह

सहायक प्रवक्ता

डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, अबोहर (पंजाब)

भारत ने स्वतंत्रता के बाद पिछले 60 सालों में कई क्षेत्रों में महान उपलब्धियां प्राप्त की है जैसे कि व्यवसाय और कृषि क्षेत्र आदि। भारत की उच्च शिक्षा में भी उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में 1950-51 में 30 विश्वविद्यालय थे 2013 तक आते—आते इनकी संख्या 712 हो चुकी है, जिससे क्रेन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, दूरवर्ती शिक्षा विद्यालय भी शामिल है। इसी तरह महाविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की संख्या भी 1950-51 के 3,970,00 के मुकाबलातन बढ़कर 2013 में करीब 1,69,75,000 तक पहुंच चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धियां सराहनीय है किन्तु अभी भी भारत का शिक्षा के क्षेत्र में और आगे जाना बनता है। अभी भी भारतीय उच्च शिक्षा के रासते में कई सारी चुनौतियां खड़ी है। अभी भी भारत की GER (Gross enrolement ratio) 21.1 प्रतिशत है जो कि विकसित देशों की 85 प्रतिशत GER से काफी पीछे है। भारत कई देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, सिगांपुर आदि की तुलना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर नजर आता है। वर्तमान शोध पत्र में भारतीय उच्च शिक्षा के समक्ष आ रही चुनौतियों को दर्शाया गया है।

भारत की उच्च शिक्षा मुख्यत: इन चुनौतियो का सामना कर रही है

गुणवता में कमी—

भारत में 2013 में 36000 के करीब उच्च शिक्षा संस्थान थे। इनमें कुछ संस्थान जैसे कि आई.टी. आई (ITI), आई.आई.एम (IIM) अपने उच्च शिक्षा स्तर के लिए व्याख्यात है। इन्हीं संस्थानों से हर वर्ष करीब 8000 विद्यार्थी निकलते है जो कि भारतीय सरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करके उनकी आवश्यकतायें की पूर्ति करते है। इतने उच्च दरजे के संस्थान होने के भी यह भारतीय संस्थान विश्व के दूसरे विश्वविद्यालयों से बहुत पीछे है भारत विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे कि हावर्ड विश्वविद्यालय, कैमब्रिज विश्वविद्यालय के निर्माण में असफल रहा है। अगर विश्व विद्यालयों में स्थान क्रम की बात की जाए तो भारतीय संस्थान पहले 100 स्थानों पर भी कहीं दिखाई नहीं देते। Q5 World University Rankings (2015-16) के अनुसार पहले उच्च स्तर के 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी संस्थान नहीं है। इस स्थान क्रम में भारत के संस्थान IIS Banglare का स्थान 147 है। इसके बाद Indian Institute of Technology Delhi है जिसका स्थान 179 है। अगर एशिया महादीप की बात की जाए तो हांगकांग, सिंगापुर, चीन, दक्षिण कोरिया के संस्थान पहले 100 स्थानों में आते है। पहले 100 स्थानों पर सिगांपुर के 2, चीन के 2, हांगकांग के दो, जापान के दो और दिक्षण कोरिया का एक विश्वविद्यालय है। भारतीय संस्थानों के पीछे रहने की वजय भारतीय शिक्षा में विश्वस्तरीय गुणवता की कमी है। भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में तो वृद्धि तो रही है किन्तु गुणवता की ओर ध्यान नही दिया जा रहा।

अध्यापकों की कमी-

भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है किन्तु उस गित से अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। जिस वजह से कार्यरत अध्यापकों के उपर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय शिक्षा संस्थानों के लिए नियम बनाने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अध्यापकों के कार्य—भार को निर्धारित किया है और साथ ही भिन्न—२ कैंडर (Cadre) के लिए

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)

Vol - III Issue-III MARCH 2016 ISSN 2349-638x Impact Factor 2.147

अध्यापकों का ढाचां भी निर्धारित किया है। यू.जी.सी. के अनुसार अगर किसी विभाग में एक पोस्ट—ग्रेजूऐश्न का कोर्स है तो उस विभाग में एक प्रोफेसर, दो उप प्रोफैसर और चार सहायक प्रोफैसर होने चाहिए। अगर उसी विभाग में दो पोस्ट—ग्रैजूऐशन कोर्स हो जाएं तो अध्यापकों की संख्या भी दुगूनी हो जाएगी। अधिकतर विश्वविद्यालयों के विभागों ने कोर्स की संख्या में तो वृद्धि कर ली अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं की। राज्य विश्वविद्यालय भी अध्यापकों की कमी की समस्या का सामना कर रहे है। राज्य सरकारें रिक्त पदों को भरने की अनुमित नहीं दे रही जिस वजह से यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।

पहुंच से परे-

भारत में उच्च शिक्षा अभी भी जनसंख्या के बढ़े भाग की पहुंच से परे है। MHRD के शिक्षा आंकड़ों (2013-14) के अनुसार भारत में वर्ष 2012-13 में कुल 26629 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया जो कि शिक्षा जनसंख्या का कुल 21 प्रतिशत है अर्थात भारत की GER (Gross Enrolment Ratio) 21 प्रतिशत है, इसके मुकाबलातन अमेरिका की 83 प्रतिशत और दक्षिणी कोरिया की 91 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में नामाकन और भी कम है। MHRD के सर्वे के अनुसार भारत में 2012-13 में कुल 3637 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों एवं 1315 पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन दिया। इनकी नामाकन प्रतिशत 11 प्रतिशत है। यह भी देखा गया है कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा ले रहे हैं वो भी आसान, सरल विषयों की ओर अधिक रूचि ले रहे है। पहले तो उनके भीतर विषयों के स्तरों के प्रति डर खत्म कर उन्हें कठिन विषयों को पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। साथ ही भारत में और संस्थाएं की स्थापना की जाए जो विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाया जा सके। कम संख्या में नामांकन भारतीय उच्च शिक्षा के सामने गंभीर चुनौती है।

उच्च शिक्षा का अंर्तराष्ट्रीयकरण-

भारतीय उच्च शिक्षा के सामने शिक्षा के अंतराष्ट्रीयकरण की भी चुनौती है। भारत के विद्यार्थी भारत में पढ़ने की बजाए दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ना अधिक अच्छा समझते है। इसका मुख्य कारण यही है कि दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवता का स्तर ऊंचा है। इसका एक और कारण भारत के किसी विश्वविद्यालय का विश्व व्याख्यात न होना भी है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारत का कोई भी शिक्षा संस्थान विश्व के सर्वोत्तम 100 संस्थानों में भी नहीं है। शिक्षा के अंतराष्ट्रीयकरण की वजह से भारत की IITs के सर्वोत्तम बुद्धजीवी विद्यार्थी भारत को छोड़कर विदेशों में पढ़ाई कर रहे है। सर्व के अनुसार भारत के विज्ञान और तकनीकी विद्यार्थी जो कि उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका आदि देशों में जाते है उनमें से 86 प्रतिशत विद्यार्थी भारत वापिस नही आते। जिस वजह से तकनीकी का विकास जो कि भारत में होना चाहिए था वही विद्यार्थी वह विकास दूसरे देशों में कर रहे है।

शिक्षा जगत का व्यावसायिक जगत से सम्बंध न होना-

भारत में शिक्षा जगत और व्यावसायिक जागत में आपसी मजबूत सम्बंध की कमी है। दोनो एक दूसरे से विमुख होने की कगार पर है। इस माहौल में न तो शिक्षा जगत की कोई खोज व्यावसाय को लाभ पहुचां रही है और न ही व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए कोई आर्थिक सहायता की जा रही है। इसी वजह से भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि उनके पास जो प्रमाण पत्र, डिगरीयां होती है उन्हें व्यावसायिक जगत न मानकर अपने मापदंडों पर उन्हें परखता है जिसमें अकसर ही विद्यार्थी फेल हो जाते है।

परीक्षा आधारित मूल्यांकन-

शिक्षा में ज्ञान, कौशलों, बोध के विकास में मूल्यांकन प्रणाली भी अहिम भूमिका अदा करती है। विकसित देशों की उच्च शिक्षा में सर्वोत्तम विकास का कारण उनकी विकसित मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी को आंकलन के कई कड़े परिक्षणों से गुजरना पड़ता है। भारत में अभी भी अग्रेंजी शासन से प्रचलित लिखती मूल्यांकन प्रणाली चली आ रही है। यह मूल्यांकन प्रणाली ज्ञानवान, कौशलयुक्त, पेशेवर वैज्ञानिक, वकील, चिकित्सक प्रशासक आदि पैदा करने में करने में अयोग्य एवं नाकाम साबित हो रही है। आज भारत को आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा

<u>Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)</u>

Vol - III Issue-III MARCH 2016 ISSN 2349-638x Impact Factor 2.147

स्तर पर मुल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाए। भारत के कुछ विश्वविधालय इस दिशा में कार्यरत भी हैं जो कि अच्छी बात है।

संबंधन प्रणाली (System Application)-

भारत की वर्तमान संबंधन प्रणाली अपनी उपयोगिता को खो चुकी है। इसे तुरंत बदलने की आवश्यकता है। भारत के सभी विश्वविधालयों ने अपने साथ कई महाविधालयों को संबंधन किया हुआ है और यह संख्या बढती ही जा रही है। विश्वविधालय से संबंधित महाविधालयों की संख्या बढने की वजह से विश्वविधालय के उपर कार्य भार भी बढता जा रहा है। इन महाविधालयों को निरीक्षण, सहयोग, नियंत्रण आदि करने के चक्र में विश्वविद्यालय प्रशासकों के पास अपनी समस्याओं को सुलझाने, अपने क्षेत्रों में खोज करने का समय कम हो गया है। दूसरा नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे है और साथ ही कई महाविद्यालय कुछ ही योग्य, विशिष्ट, स्वतंत्र महाविद्यालयों को ही प्रदान किया जा सकता हैं किन्तु वर्तमान में संबंधन प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका हैं जिस महाविद्यालयों को संभावित विश्वविद्यालय अनुदान किया है उनमें से अधिकतर महाविद्यालय राजनीतिक लोगों के मलिकयत के है। वर्तमान में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की समिति ने 44 इसे महाविद्यालय के विरूद्ध कारवाई की है जो कि संभावित विश्वविद्यालय बनने के हकदार नही थे। दूसरा शिक्षा समवरती सूची का विषय है अर्थात् यह राज्य सरकार के अधीन भी आती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कई राज्यों ने अपने राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमित दे दी जिनमें अध्यापकों की भारी कमी है एवं जिनमें मूलभूत ढाचां ही नही है।

राजनीतिक हस्तक्षेप-

भारत में अधिकतर शिक्षा संस्थान राजनीतिक नेताओं के है। धीरे—धीरे यह राजनीतिक हस्तक्षेप विश्वविद्यालय में बढ़ रहा है। प्रत्येक राजनीतिक संगठन ने विश्वविद्यालयों में अपने—अपने युवा संध बनाए हुए है। राजनीतिक नेता विद्यार्थियों की ताकत को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे है। विश्वविद्यालयों में इनका हस्तक्षेप इतना हो चुका है कि अधिकतर नियम इनके द्वारा बनाए जा रहे है। शिक्षा क्षेत्र का कोई व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण इनके द्वारा निर्धारित पाठ्य क्रम, अध्यापन विधियां, नियम आदि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवता को क्षित पहुंचा रहे है। अधिकतर विश्वविद्यालयों का पाठ्कक्रम इस प्रकार का हो चुका है कि समाज की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों से कोसो दूर है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ विद्यार्थी प्रमाण पत्र तो प्राप्त कर लेते हैं किन्तु नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। नियम बनाने वाले इन नेताओं के द्वारा निर्धारित शिक्षण विधियां इस प्रकार की हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना को रिक्त कर देती हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय अपने अध्यापकों को अपना अध्यापन रूचिपूर्ण बनाने के कोई निर्देशन, सिखलाई प्रदान नहीं करती। अगर बुद्धिजीवी अध्यापक वर्ग शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए कोई परामर्श देता है तो उसकी बात तक नहीं सुनी जाती। इसी वजह से आज भारत में खोज (Research) का इतना बुरा हाल है। अगर कही खोज़ की भी जा रही है तो वह वर्तमान में समाज द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं से दूर, आर्थिक—सांस्कृतिक आवश्यकताओं से दूर है।

शिक्षा का महंगा होना-

भारतीय उच्च शिक्षा के सामने एक गंभीर चुनौती शिक्षा का महंगा हो जाना भी है। विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस, शिक्षा फीस, होस्टल फीस, किताबों के ऊपर एवं रहने—खाने के उपर खरचा करना पड़ता है जो कि पिछड़े गरीब विद्यार्थियों की पहुंच से परे है। भारत के बजट में भी शिक्षा के उपर कम पैसा खर्च किया जाता है। भारत की शिक्षा GDP 3.3 प्रतिशत है जो कि विश्व स्तर पर 4 प्रतिशत और BRICS देशों में 5 प्रतिशत है। भारत में उच्च शिक्षा में विद्यार्थी नांमाकन की दर बढ़ती जा रही है किन्तु प्रति विद्यार्थी खर्च कम होता जा रहा है। विकसित देशों में विद्यार्थी के लिए बैकों द्वारा दिए जा रहे कर्ज उपर ब्याज दर भी कम है। किन्तु भारत जैसे विकसित हो रहे देशों में ब्याज दर अधिक है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो इसके उपर खर्च करना राज्य एवं क्रेन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है। यहीं समसया उत्पन्न हो रही है। क्रेन्द्र सरकार राज्य विश्वविद्यालयों के खर्च को राज्यों का उत्तरदायित्व मानती है तो राज्य अपने जिम्मेवारी से बचते हुए क्रेन्द्र सरकार से पैसे की मांग करते रहते है। भारत में

<u>Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)</u>

Vol - III Issue-III MARCH 2016 ISSN 2349-638x Impact Factor 2.147

शिक्षा में प्रति विद्यार्थी खर्च और उस खर्च की पूर्ति के लिए बजट में पैसों के प्रावधान में भारी अंतर है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से यह चुनौती और गंभीर होती जा रही है।

निष्कर्ष—

वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, इसमें प्रमुख है शिक्षा में गुणवता की कमी का होना, उच्च स्तर पर अध्यापकों की कमी होना, उच्च शिक्षा का विद्यार्थियों की पहुंच से दूर हो जाना आदि है। उच्च शिक्षा का अंतराष्ट्रीय होने से भारतीय विद्यार्थी दूसरे देशों में जा रहे है। शिक्षा क्षेत्र और व्याववसायिक क्षेत्र में सम्बन्ध कम है। भारत में उच्च शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली अपनी उपयोगिता खो चुकी है। आज इन चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ बाते करने की बजाए काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म किया जाना चाहिए एवं नये, मौलिक, रचनात्मक विचारों को जगह देनी चाहिए। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के नामाकन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। बजट में शिक्षा GDP को बढ़ाना चाहिए। विश्वविद्यालयों के साथ महाविद्यालय की संबंधन प्रणाली में सुधार हो एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को विश्वविद्यालय में गुणवता बढ़ाने एवं दोषों को दूर करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। उच्च शिक्षा में गुणवता की बढ़ौतरी से ही भारतीय विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय हो सकते हैं।

संदर्भ

- 1. MHRD (2006) Annual Report. Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary and Higher education. Government of India. New Delhi.
- 2. Higher Education in India: Issues, Concerns and New Directions http://www.ugc.ac.in/pub/heindia.pdf.
- 3. University News,51(50). No. 31, Dec.16-22,2013
- 4. http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015
- 5. MHRD (2014). Educational Statistics At a Glance, Ministry Of Human Resouce
 Development Bureau Of Planning, Monitoring & Statistics. Government of India, New Delhi.
- 6. https://www.linkedin.com/pulse/ Karan kyanam-problems-with-the-indian-education-system

